Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 17 अंक 07 30 जूलाई 2017 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

अन्नदाता से कर्जदार बना – बेचारा किसान

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

आरंभ से ही बेपरवाह राजनैतिक तंत्र से परेशान रहा बेचारा किसान अब एकजुट होने लगा है और परिणामस्वरूप कई राज्यों में किसान आंदोलन शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आदि सरकारों ने किसान हित में कोई कारगर उठाने की बजाये इसे हल्के में लिया और जब यह आंदोलन हिंसक होने लगा तो पहले तो विपक्ष को कोसा, फिर चिर-परिचित राजनीति शुरू हुई, टाल-मटोल, धरना, नाटक जैसे अनेकों हथकंडे अपनाए गए लेकिन ना किसी ने समस्या जानने का प्रयास किया और ना ही समाधान का क्योंकि नाशुरापन मानवता का अभिन्न अंग है।

वर्ष १९६५ के भारत पाक युद्ध के समय जब देश अन्न के लिए दूसरों पर निर्भर था तब 'जय जवान, जय किसान' का नारा लगा। किसान ने कर दिखाया लेकिन जनता ने दोनों को नकार दिया। किसान ने उपज तो बढ़ा दी जिससे कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत में तो बढौतरी लाजिमी थी लेकिन उसके अनुपात में उसकी विक्रय कीमत नहीं बढ़ी। उस पर भी विडंबना है कि कमीशनखोरों को ही लाभ होता है। फसल की उत्पादकता बढ़ जाए तो कीमत गिरा दी जाती हैं, मतलब फसल कम हो या ज्यादा, नुकसान किसान का ही है।

किसान को सदा याचक की दशा में रखा जाता है, खाद बीज लेने जाए तब भी और फसल बेचने जाए तब भी और ऋण की तो बात ही अलग है। किसान अहसान फरामोश या भिखारी नहीं है, खुद्दार है, जिसे कर्ज माफी इत्यादि की जरूरत नहीं है अलबता फसल के उचित दाम और वक्त पर मिले तो वह इसमें भी खुश है। उसने बीज, खाद, पानी, बिजली, कीटनाशक की मांग की, उसके लिए बाजार से सभी चीजें नदारद और वह आढ़ती के आगे हाथ पसारे, याचक मुद्रा में खड़ा रह गया। आढ़ती ने मनमाने भाव पर उसे बेचा और फसल बंधक बना ली, जिसे औने-पौने भाव पर खरीदा और नतीजा अन्नदाता को याचक बना दिया और कर्ज दर कर्ज उसकी गर्ज-मर्ज पर बढ़ने लगा क्योंकि किसानी आज भी पूर्णतया मौके के भरोसे ही है। कहीं डूबा है तो कहीं सूखा। आज आधे से ज्यादा भारत बाढ़ से ग्रस्त है। किसान के जान माल को खतरा है दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा सूखे की चपेट में हैं। किसी को किसान को सुध लेने की फुरसत नहीं है। फसल लागत कीमत में बढौतरी के और भी कई कारण हैं। सर्वोपरि जोत है जो दिन-ब-दिन छोटी होती जा रही है और पुश्तैनी भूमी का बंटवारा हो रहा है, जिससे एक परिवार का गुजारा नहीं होता। समाधान हो सकते हैं। वर्ष १९९९-२००० में कुल १८९.७ मिलीयन हैक्टयर कृषि भूमि में से फसल चक्र १४१.२ मिलीयन हैक्टयर में ही था। प्रति जोत औसत १९७०-७१ कि २.२८ हैक्टयर से कम होकर १.८२ हैक्टयर और १९९५-९६ तक मात्र १.५० हैक्टयर तक सुकड़ गया। बिहार, केरल, बंगाल तथा उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में तो अब औसत मात्र ०.५ हैक्टयर रह गया। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान इत्यादि में राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक ४ से ७.१५ हैक्टयर कृषि जोत में है।

१० हैक्टयर से उपर जोत मात्र १.६ प्रतिशत ही है जो कि कुल १७.४ प्रतिशत कुल जोत क्षेत्र का भाग है, यही नहीं १९९०-९१ तक पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश में चकबंदी की गई ताकि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी पुस्तैनी भूमि को एक स्थान पर करके जोत के काबिल बनाया जा सके। इससे रास्ते भी खेत तक पहुंचाए गए ताकि मंडीकरण की असुविधा का भी हल निकाला जा सके। उसके साथ सहकारी कृषि को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे कुछ किसान मिलकर कृषि करने लगे और खेत भी जोत के काबिल हुई तथा आधुनिक तकनीक, बीज, खाद व कीटनाशकों की भी व्यवस्था संभव हो सकी। इसमें जोत मलकियत के हिसाब से बंट जाता था, जो केरल इत्यादि राज्यों में सफल हो रहा है। कृषि में बीज की बहुत महत्ता है लेकिन दुख की बात है कि बीज अधिकतर लघु एवं सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर है क्योंकि बहुत मंहगा है। भारत सरकार ने १९६३ में राष्ट्रीय बीज निगम तथा १९६९ में भारतीय किसान निगम की स्थापना की गई ताकि उत्तम बीज की उपलब्धता करवाई जा सके। वर्ष १९६६-६७ में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने हेतू उच्च उत्पादकता कार्यक्रम शुरू किया गया। केवल हरियाणा में खाद्यान्न उत्पादन ४.५ लाख टन से बढ़कर कुछ वर्षों में १२५ लाख टन तक पहुंच गया। खादान्न में हरियाणा दूसरों की निर्भरता से उभर कर अन्य राज्यों को

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

खादान्न देने में समर्थ हो गया। इससे उसकी लागत भी बढ़ी, जिससे आज किसान घाटे की बेचारगी में जी रहा है। आज भी उत्तम बीज की उपलब्धता केवल संपन्न किसानों की पहुंच में ही है। लघु तथा सीमांत किसानों के हिस्से नकली बीज, खाद और कीटनाशक ही पहुंच रहे हैं और वे भी मनमानी कीमत पर। किसान दोहरी मार खा रहा है और अन्नदाता से कर्जदाता बनता जा रहा है। किसान आत्म हत्याओं का एक सर्वोपरि कारण यही ऋण और ब्याज के चक्र में निहित है। तथ्यों की जुबानी ही देख ले कि उत्तम बीज उपलब्धता 2001-02 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 तक 9.5 तक हो पाई। बाकी किसान तो अपने पारंपरिक स्त्रोतों या नकली खरीद के भरोसे ही हैं।

आज रासायनिक खाद व बायो कीटनाशकों की भी महता है क्योंकि पारंपरिक तरीकों और साधनों से उत्पादकता कम हुई है। भूमि पर उर्वरता में भी कमी आई है क्योंकि साधनों की कमी है। उत्पादकता विश्व के न्यूनतम स्तर पर है, यहां भी मांग और वितरण में अंतर है। भोले किसान ने बिना सोचे समझे जरूरत से अधिक रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का उपयोग किया क्योंकि आढ़ती ने अपने लाभ हेतू उसे अधिक प्रयोग करवा दिया, जिससे भूमि का पानी भी जहरीला हो गया है। यह अभी तक भी जारी है क्योंकि कीटनाशक उत्पादकों ने आढ़ती को बिक्री इंनसैटिव देते हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र में तो कैंसर का प्रकोप बढ़ गया है। राजस्थान में कैसर का सस्ता उपचार हो रहा है और इस क्षेत्र से जाने वाली रेलगाड़ी का नाम ही 'कैंसर रेल' पड़ गया है। हम ऐसे गलत व्यापार का निशाना भोले किसानों को तो बना ही रहे हैं लेकिन खुद भी वही अनाज खा रहे हैं, जिसके लिए जागरूकता नितांत जरूरी है। आज आर्गेनिक खेती की बात तो चली है, प्रोत्साहन भी मिला है। उचित बीज, खाद, बायो कीटनाशक तथा मंडीकरण का जिम्मा भी लिया जा रहा है लेकिन उत्पादकता और वितरण दोनों आम आदमी की पहुंच से अभी बाहर है और आपूर्ति भी नगण्य के बराबर है।

संसाधनों की कमी के साथ-साथ पूर्ण उपयोग भी अभी नहीं हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार 6500 टन शहरी क्षेत्रों में तथा 1600 टन ग्रामीण क्षेत्रों में कंपोस्ट का उचित प्रबंधन तथा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी और गंदगी से भी छुटकारा मिल सकेगा। सब्सिडी का राग सारी सरकारें गाती हैं लेकिन कभी किसी ने यह जानने तक का प्रयास नहीं किया कि यह किसान तक पहुंच भी रही है या रास्ते में ही गायब हो रही है। सच्चाई यह है कि यह भ्रष्टाचार और आढ़ती की भेंट चढ़ रही है।

सिंचाई खेती की जान है लेकिन मात्र एक तिहाई क्षेत्र ही सिंचित हैं जो विश्व में चीन के बाद दूसरे नबंर पर है। अभी भारत, इजरायल से पानी प्रबंधन तथा फसली चक्र की तकनीक सीखने की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री का ही हाल का दौरा क्या रंग लाएगा, यह अभी दूर की कोड़ी है। हां, यह तथ्य प्रमाणित होता जा रहा है कि भविष्य में बर्चस्व पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र का ही होगा। भारतीय किसान अपनी कर्मठता से यह भी संभव कर देने में सक्षम है, अगर उसे आगे बढ़ने दिया गया अन्यथा दूसरी स्कीमों की तरह टांय-टांय फिस भी हो सकता है।

''हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम ए गुलिस्तां क्या होगा?'' यदि सूझबूझ से चले तो भारत का भविष्य उज्जवल है। मात्र मिडलमैन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जरूरत है। किसान अपनी बेचारगी के सभी धोने धो देगा। आज कृषि मशीनरी उसकी पहुंच से बाहर है तथा मानव श्रम उसे मंहगा पड़ता है और इसीलिए उसकी उत्पादन कीमत अधिक है। किसान अपनी कर्ज-मर्ज-गर्ज के चलते मंडीकरण की असुविधा का भी भुगतभोगी है। वह अपना उत्पादन कुछ दिन भी भंडारण नहीं कर सकता और गांव देहात में ही औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। मिलीभगत से बैंकों से ऋण मिडलमैन किसान के नाम से ही सस्ते दर पर लेकर उसी को मंहगी दरों पर उपलब्ध करवाता है। यह ब्याज दर 20 से 30 प्रतिशत तक होती है इससे किसान इस ब्याज की दलदल में उलझता जा रहा है।

यूरोपियन यूनियन अपने सभी देशों के किसानों ने एक संगठन कायम किया, जो जरूरत के अनुसार खाद्यान्न उत्पादित करते हैं। कुल उत्पादन क्षेत्र के अनुसार फसल का बंटवारा हो जाता है। खाली रही भूमि वाले किसान को मुआवजा दिया जाता है। अधिक उत्पादन हो जाने पर अनाज समुद्र तक में गिरा दिया गया, जिसकी अब नौबत नहीं आती क्योंकि उन्होने पूर्व अनुमान से ही उत्पादकता की दूसरी वहां फार्म पर मशीनीकरण से उत्पादकता लागत में कमी लाई गई है। मानव श्रम कम से कम है जो निराई, मुड़ाई और तुड़ाई तक सीमित है।

भारत में किसान पर राजनीति हो रही है तथा मनरेगा गरीब मजदूरों हेतू है लेकिन अधिकतर वे ही इस लाभ से वंचित हैं। कृषि उत्पादकता सूखे की मार से थम सी गई थी। उत्पादकता 2015-16 में 1.2 प्रतिशत ही रही जो अब बढ़कर 4.1 प्रतिशत 2016-17 में हुई है लेकिन नोटबंदी की मार भी किसान ने झेली, जिस कारण उसे अपना उत्पाद औन-पौने दामों पर बेचना पड़ा क्योंकि उसकी मजबूरी थी। इस अवधि में कर्ज की मार बढ़ी क्योंकि आढ़ती ने 20 प्रतिशत तक ब्याज वसूला और मजबूरी में किसान भूमि बेचकर अपने ऋण का भुगतान किया, जिससे आगे से उसका भूमि संसाधन समाप्त ही हो गया।

धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह सर्वश्रेष्ठ है। –वेद व्यास

आज किसान हितैषी का नारा देने वाली सरकारों की कथनी और करनी में अंतर है। हरियाणा कृषि विभाग के सौजन्य से पी0एम0 फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों को लाभ देने हेतू फसल बीमा प्रीमियम दर गत वर्ष की तुलना में चार गुणा तक बढ़ा दी है जो कि खरीब फसलों पर 120 रूपये से लेकर 430 रूपये प्रति हैक्टयर तथा रबी फसलों के लिए 82.50 रूपये से लेकर 128 रूपये फसल के अनुसार अधिक काटे जाएंगें। तर्क यह है कि बैंकों ने किसानों की प्रति एकड़ ऋण में वृद्धि कर दी है। भारत में आज किसानों पर 12 लाख 60 हजार करोड़ का ऋण है, जिसका ब्याज तक चुका पाना कृषकों की कमर तोड़ रहा है, जिससे साल भर में करीब 1200 किसान आत्महत्या करते हैं। यह बात भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में लिखित में दी है और वास्तव में यह गिनती इससे भी अधिक है क्योंकि फसल अधिक हो या कम, नुकसान किसान का ही होता है।

अब भी हालात दिन प्रति दिन बद से बदत्तर हो रहे हैं। किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे अग्रणीय है। वर्ष 2004 में 4147, वर्ष 2005 में 3926, वर्ष 2013 में 3146 आत्महत्याएं हुई। केवल हरियाणा में अप्रैल 2015 में 4 आत्म हत्याएं हुई। एक अनुमान के अनुसार गत 20 वर्षों में 348538 आत्महत्याएं हुई अर्थात 45 रोजाना। क्या सरकारें सो रही हैं या इंसानियत मर चुकी है? किसान काश्तकार वर्ग की सुध लेने की अत्यंत आवश्यकता है। यह असंगठित दिखते हैं लेकिन यह धधकते अंगारे हैं क्योंकि काम करने का जुझारूपन इसी से ही आता है। खुदा न खास्ता यह लावा फूट गया तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसकी परिणिती देख चुके हैं। एक बार तो संभल गया लेकिन इस समस्या का स्थाई हल निकालना नितांत जरूरी है।

पंजाब सरकार द्वारा ऋण माफी का ऐलान किया तभी पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला का एक अध्ययन सामने आया कि कृषि क्षेत्र विस्फोट के कगार पर है। विश्व में नाम कमाने वाले किसान की हालात मजदूर से भी बदतर हो रही है जो कृषि में बढ़ती लागत और गिरती कीमतों की वजह से हो रहा है। आज 86 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तथा 80 प्रतिशत मजदूरों का भी यही हाल है। सीमांत किसानों पर प्रति एकड़ 65 हजार का कर्ज है। लघु किसान पर 55000 यानि करीब 32 प्रतिशत सीमांत किसान गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं।

खाद आपूर्ति वाली तीन बड़ी कंपनियों का लाभांश 2016-17 में 1255 करोड़ था जो 2015-16 के अनुपात में 37 प्रतिशत अधिक है। कीटनाशक आपूर्ति की तीन बड़ी कंपनियों को 2016-17 में 900 करोड़ का लाभ हुआ, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में बीज आपूर्ति वालों का लाभ 85 करोड़ तथा ट्रैक्टर वालों का लाभ 5300 करोड़ रूपये हुआ। आखिर किसान कब तक इस सुनियोजन लूट का शिकार होकर बेचारगी को ढ़ोता रहेगा। यहां बताना तर्कसंगत हो गया है कि पूर्व सरकारों ने भी लूट ही मचाई थी और अब उनके घड़ियाली आंसूओं से किसान की समस्या का हल निकलने वाला नहीं है, जिसके लिए ठोस कदम उठाने होगें।

किसान अभी भी नोटबंदी के देश से उभरा नहीं है कि जी एस टी का नाग उसे लील रहा है। कृषि संयत्रों का साईज 32 हजार करोड़ से उपर है, जिसमें 1.50 लाख बड़ी ईकाइयां तथा 300 लघु उद्योग केवल पंजाब में ही हैं। इन पर 12 प्रतिशत जी एस टी आयत है, जो कृषि उद्योग को सीधी मार मारेगी। सरकार ने यह 5 प्रतिशत किया है ताकि किसान को कुछ राहत मिल सके क्योंकि उत्पादक तो यह बढ़ौतरी किसान से ही वसूलेगें।

किसान अकेला ही नहीं अपितू उसका पूरा परिवार कृषि घाटे से आहत है। हालांकि किसानी में पुरूषों का प्रभुत्व माना जाता है लेकिन 1989 की श्रमशक्ति रिपोर्ट कुछ अलग ही बयां करती है क्योंकि 80 से 100 मिलीयन स्त्रीयां खेती-किसानी से जुड़ी हुई हैं। बीज की संभाल, फसल की बुआई, छंटाई, रोपाई, निराई, कटाई, कढ़ाई में स्त्री का बर्चस्व है। यही नही फल और सब्जियों की खेती में भी औरतों की बहुतायत है। इक्कसवीं सदी का सच यहीं है कि आज 32.8 प्रतिशत स्त्रीयां इस कार्य में कार्यरत हैं, जिनके बिना कृषि संभव नहीं है इसलिए उनके योगदान को कम आंकना उचित नहीं होगा।

किसान अपनी बदहाली और बेचारगी की वजह से कृषि से बेमुख हो रहा है, जो समाज की सेहत के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। जिस देश का बचपन भुखा हो तो उसकी जवानी क्या होगी? महाराष्ट्र में 2015 में 75 प्रतिशत कम बरसात हुई। सरकार ने 10512 करोड़ का पैकेज तो दिया लेकिन कर्जमाफी का वादा तो वादा ही रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई है जिसे सरकार 50 प्रतिशत तक पहुंचना चाहता है जो अभी तक मात्र 3.8 प्रतिशत को ही उपलब्ध है। किसान का भला स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने और लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने पर ही किसान की स्थिति ठीक होगी अन्यथा बारूद के ढ़ेर पर बैठा किसान उड़ गया तो किसी का भी भला नहीं होगा। जहां अन्नदाता ही बेचारा हो तो देश की हालत किसी से छूप नहीं सकती।

डा0 महेन्द्र सिंह मलिक
आई.पी.एस., सेवानिवृत,
प्रधान जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला एवं
अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति

सन्यास हृदय की एक स्थिति का नाम है। न कि किसी नियम या वेशभूषा का। –अज्ञात

किसान मसीहा दीन बंधु सर छोटूराम के विरूद्ध सांसद श्री राजकुमार सैनी द्वारा की गई अपमानजनक व अमर्यादित ब्यानबाजी

प्रिय भाई व बहनों

मैं इस प्रकाशन के माध्यम से सांसद, श्री राजकुमार सैनी द्वारा जनप्रिय एवं किसान मसीहा दीन बंधु सर छोटूराम के विरूद्ध 17 जुलाई 2017 के दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित करवाई गई अपमानजनक, अमर्यादित व तुच्छ मानसिकता की ब्यानबाजी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसमें समाज की केवल एक विशेष जाति के साथ-साथ दीन बधुं सर छोटू राम के प्रति उनकी घटिया सोच व मानसिक दिवालियापन स्पष्ट नजर आता है।

यह सर्वविदित है कि दीन बंधु सर छोटू राम किसान, कामगार व मजदूर वर्ग के हितों के लिए सदैव संघर्षरत रहे। अतः उनको जाति विशेष के साथ जोड़ना उनका सरासर अपमान है। उन्होने अपने कार्यकाल में किसानों के हित में बहुत सारे कल्याणकारी कदम उठाए जिनमें किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाकर उनकी जमीनें वापिस दिलवाई। वर्तमान में भाखड़ा नंगल परियोजना की परिकल्पना भी उन्ही की देन है और उनके द्वारा किसान कोष स्थापित किया गया जिससे हर वर्ग को शिक्षा मिली और शिक्षा का विस्तार हुआ। यही नहीं, उन्होने संयुक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खान की उपस्थिति में अंबाला में जनसभा के दौरान किसान की फसल की कीमतें बढ़ाने के लिए पुरजोर सिफारिश करते हुए कहा था ''जिस खेत से दो जून की रोटी ना हो मयसर, उस खेत की गोसाय गंदम को जला दो'' जो कि उनके किसान-मजदूर के प्रति संवेदना को प्रकट करता है। इसी प्रकार किसान-मजदूर वर्ग की दशा के सुधार हेतू सरकार का विरोध जताते हुए यहां तक कहा था कि ''नहीं चाहिए मुझे मखमल के मकबरे, मुझे तो मिट्टी का हर्म दिलवा दो।'' इस किस्म के जनप्रिय व्यि1तत्व की आलोचना करना उनका ही नहीं बल्कि समस्त किसान व मजदूर वर्ग का अपमान है।

सांसद श्री राजकुमार सैनी आरंभ से ही राष्ट्र की सभी अन्य बिरादरियों के सिवाय केवल एक विशेष वर्ग के प्रति द्वेषपूर्ण व हिंसक बयानबाजी करके प्रदेश में व्याप्त परंपरागत आपसी भाईचारे को खत्म करने पर उतारू रहे हैं। इनकी दूर्भावनापूर्ण बयानबाजी से प्रभावित जाति विशेष द्वारा समय-समय पर विरोध जताने पर भी सरकार द्वारा इनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है जैसे कि नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधान सभा, चौधरी अभय सिंह चौटाला द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को पत्र लिखकर सांसद श्री सैनी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आग्रह किया जा चुका है। **इसके साथ ही जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा राष्ट्र की सभी जाट संस्थाओं/संगठनों, खाप-पंचायतों, स्वयं सेवी संस्थाओं व समाज के बुद्धिजीवीयों से सांसद श्री सैनी द्वारा जाति विशेष के विरूद्ध किये जा रहे दुषप्रचार से अवगत कराने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है।**

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सांसद श्री राजकुमार सैनी द्वारा जाति विशेष के खिलाफ लगातार की जा रही भड़काऊ व द्वेषपूर्ण बयानबाजी व दीन बंधु सर छोटू राम के विरूद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी के कारण इनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत अपराधिक मुकदमा दर्ज करने व कठोर कार्यवाही करने के लिए एकजुट होकर केंद्र व हरियाणा सरकार से कार्यवाही हेतू आग्रह करें ताकि इनकी बेलगाम बयानबाजी के कारण प्रदेश में सामाजिक भाईचारा खराब ना हो और सामाजिक तथा कानून व्यवस्था बनी रहे।

आपका,

(डा0 महेंद्र सिंह मलिक)

भा.पु.से. (सेवा निवृत)

प्रधान, जाट सभा चंडीगढ़/पंचकूला

जिसके पास विद्या रूपी नेत्र नहीं है, वह अंधे के समान है। –अज्ञात

Police Reforms-Need of the Day

Dr. Sarita Malik, H.C.S.
An Expert on Police Sub-Culture- Police Psychology

The strength of a democracy and the quality of life enjoyed by its citizens are determined in large measure by the ability of the police to discharge their duties. Policing, without doubt, is a very vital aspect for the existence of a society, but it is as a unit, target of criticism by all and sundry, including intellectuals, jurists, social activists, media, politicians and citizens. Many people believe that the police at times shield criminals, refuse to register complaints, fabricate false cases against innocent victims and frequently resort to "padding & illegal" detentions at police stations.

Serious role conflict always exists in policing, particularly between ideals of crime control and ideals of due process. But it is ignored that limitations of our criminal justice system hamper efficient and effective functioning of police and this is compounded by the attitude in the society which judges the police effectiveness on the basis of achievement of goals and its outcomes. The situation becomes more complex because of the prevailing core police sub culture which makes them think no one understands them. Thus they are loyal to each other and have to fight crime only by bending the rules, even as the public remains too demanding and unsupportive. Further, police resorts to extra judicial methods during investigation as there are inadequacies in the relevant legislations; increasing number and changing nature of the crime; and, too much expectations of the public from the police. Thus, police today is a beleaguered institution which has lost a clear sense of identity.

Likewise, there are certain glaring examples which portray police brutality such as the merciless lathi charge on the empty handed Honda workers in Gurgaon, now Gurugram, on 25 July, 2005 which was highlighted by several T.V. channels. Moreover, custodial crimes, including rapes, murders etc. are a routine phenomenon for the police in India. For want of sincerity and sensitivity on the part of police, not only the law and order situation has suffered but also the overall performance of police has come under severe fire, particularly over Nirbhaya & Talwar cases of Noida. Interference of those in seats of power and extortion are also frequently reported.

While these perceptions are hard to refute, there are genuine problems faced by the police force. Foremost is the ruler-supportive ethics that is still dominant, which encourages the police to do the bidding of the political leadership rather than to stand as impartial guardians of the people's democratic rights. As a consequence on many occasions the decision to arrest is made on political considerations rather than as a means to deal with the crime phenomenon. Transfers and postings of officers of all ranks, at the behest of political leadership, hampers the ability of the police leadership to discipline officers. In addition, lack of functional autonomy and absence of an environment that encourages living up to ideals pushes a police officer towards a state of apathy. Simultaneously, absence of direct accountability to people pulls them towards corrupt practices.

Deb, Chakraborty, Chatterjee & Srivastava found in a study on Kolkata traffic police that the major problems faced by them while discharging their responsibilities were anxiety due to tense situation 62.5%, followed by unnecessary case pressures 44.6%, political pressure and interference 42.8%, lack of manpower 41.1%, pressure from discharging duties 32.14%, non-cooperation from the public 30.36%, lack of infrastructure 26.8% and non-cooperation from higher authorities, 17.9%. It is also poorly funded, and all material acquisitions have to be procured by seeking government grants tailored to a specific need and only a limited amount is provided for general maintenance of vehicles, buildings, communication equipment and uniform and stationary etc.

It is often forgotten by the society that while signing up to the police services, the personnel do not give up their basic human rights. Humane conditions of work, which are pre-requisite, are normally denied to them. The overall work environment of police, particularly of subordinates and middle rank officers is dehumanizing and de-intellectualizing. Ironically, the police personnel who are obliged to protect and uphold the human rights

of others are themselves the victims of the violation of their human rights in the form of undue long working hours, leave problems, denial of family life, denial of social life, delayed promotions, inadequate infrastructure, poor salaries etc. Securing their human rights will undoubtedly enable them to protect, help and reassure the citizens in a better way.

The service conditions of the police persons, especially those of the Constabulary are poor and unsatisfactory. The police can never succeed if it is not educated, intelligent and properly trained to discharge its duties sincerely. In recent times, the number of policemen has multiplied but their educational and training standards and public dealings remained more or less the same as during the British period. The average working hours of a police person are much more than any other government servants as no fixed duty hours are there. A policeman often has 24-hour workday and limited number of holidays thus hardly getting any time for his family.

The pay and allowances of the constabulary are very meager and the speedy increase in inflation rate has made their position more deplorable. Further, inadequate chances of promotion and overwork in the department due to shortage of staff also add to their frustration and anger as the environment in which the police is working is not congenial. Moreover, the ever increasing demand for VVIP/VIP security causes a big drain on meager police resources.

With these glaring weaknesses of the system, it is not a surprise that the Indian Evidence Act is heavily loaded against the police force making its task of securing successful prosecution almost impossible. Fortunately, today it is being recognized that the Police Act that governs our force is obsolete and needs radical changes. In this direction, the Supreme Court judgment of September 23, 2006, was a milestone. It has virtually overhauled the Indian Police Act 1861. But the biggest challenge is its implementation. Any dilution would be self defeating and immensely harm the society that has become more complex and demanding, but delay in implementation is equally harmful.

किसान खुदकुशी का भयावह मंजर

– ज्ञान प्रकाश पिलानियां, पूर्व सांसद, जयपुर

यह दहलाने वाली खबर है कि पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में किसानों की खुदखुशी के हालात भयावह हैं। पंजाब के तीन विश्वविद्यालय के एक सर्वे की मानें तो 2000 से 2010 के बीच 6,926 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से 3,954 किसान और 2,972 खेती से जुड़े मजदूर थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 16 मार्च को कार्यभार संभाला। इन गत तीन महिनों में 37 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर किसान कर्ज में डूबे हुए थे। इन तीन महीनों में मानसा, बंठिंड़ा और बरनाला जिलों में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी की घटनाएं हुई हैं। मानसा और बठिंड़ा में 8, बरनाला में 6 किसानों ने आत्महत्या की हैं। खुदकुशी की घटनाएं रोकने के लिए सीएम अमरिंदर ने विधान सभा चुनाव के दौरान नारा दिया था, 'कर्ज कुर्की खत्म, फसल दी पूरी रकम'। गरीब किसान कर्ज में ही रहने को मजबूर है, जो हर साल बढ़ता ही जाता हैं। पंजाब में ही 98 फीसदी ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हैं और इनमें से 94 फीसदी की आमदनी से ज्यादा खर्च हैं। पंजाब में अनुमानित 35000 करोड़ रुपये का लोन किसानों पर बकाया है।

अग्रस्तता के कारण किसानों को आत्महत्याओं के संबंध में लोकसभा के 12 सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 903 के उत्तर में प्रकट किया गया था कि 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 में 5650 किसानों ने आत्महत्या की जो वर्ष 2015 में बढ़कर 8007 हो गई। आत्महत्याओं में 47.7 फीसदी वृद्धि हुई।' इस प्रकार एक दिन में आत्महत्या करने वालों की संख्या 21. 93 है। यह भयावह स्थिति है कि पिछले 21 वर्षों के दौरान 318000 किसानों ने आत्महत्या की हैं। राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी. आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार हर 41वें मिनट कहीं न कहीं एक किसान आत्महत्या करता हैं। कर्ज नहीं चुका पाना किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मुख्य कारण बनकर सामने आया हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 तक के आंकलन के अनुसार देश में 51.9 प्रतिशत किसान परिवार ऋणी हैं। 30 सितम्बर 2016 तक देश के किसानों पर बकाया ऋण राशि 12.60 लाख करोड़ रुपये थी। सर्वेक्षण के अनुसार, जिस दिन किसान परिवारों पर कर्ज के आंकड़े लिए गए थे, उस दिन प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन लगभग 47000 रुपये कर्ज होने का अनुमान लगाया गया है इस ऋण में संस्थागत संस्थानों तथा सेठ–साहूकारों से लिए गए कर्ज भी शामिल हैं। कम जोत के किसान परिवार पर कम कर्ज का भार है जबकि बड़े किसान परिवारों पर अधिक कर्ज है। कम जमीन वाले 41.9 प्रतिश किसानों पर कर्ज है। जबकि 10 हैक्टेयर से कम जमीन वाले 78.7 प्रतिशत किसान परिवार कर्जदार हैं। एक हैक्टेयर से कम जमीन वाले किसान परिवार पर औसतन 31100 रुपये का ऋण है जबकि 10 हैक्टेयर से अधिक जमीन जोतने वाले किसान परिवार पर लगभग 29300 रुपये का कर्ज है। आत्महत्या करने वाले किसानों में करीब 80 फीसदी बैंक

जिंदगी की जिम्मेदारी कोई बोझ की चीज नहीं है। वह आनंद से ओत–प्रोत है। –विनोबा भावे

कर्ज के बोझ से दबे थे न कि महाजनों से। गैर संस्थागत संस्थाओं या सेठ–साहूकारों ने 25.8 प्रतिशत कर्ज किसानों को दिया है।रुपये 57700 रुपये महाराष्ट्र में औसत कर्ज प्रति किसान परिवार था।?

आज आम किसान के कर्ज की समस्या, मीडिया में सुर्खी में आ गई है। इस संदर्भ में, कर्जे के आकंड़े ज्ञातव्य हैं। 46848100 कर्ज से दबे किसान परिवार देश में हैं। इनमें से 10 प्रमुख राज्यों में परिवारों की संख्या है :– उत्तर प्रदेश में 7908100, महाराष्ट्र में 4067200, राजस्थान में 4005500, आंध्रप्रदेश में 3342100, पश्चिम बंगाल में 3278700, कर्नाटक में 3277500, बिहार में 3015600, मध्यप्रदेश में 2741400, तमिलनाडु में 267800 और ओडिशा में 2583000 परिवारों पर 30 सितम्बर 2016 तक 12.60 लाख करोड़ कुल कृषि कर्ज था। जिसमें से 7.75 लाख करोड़ क्रॉप लोन एवं 4. 85 लाख करोड़ टर्म लोन था। बैंकों के आधार पर विभाजन था – 1.45 लाख करोड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1.58 लाख करोड़ सहकारी बैंक और 9.57 लाख करोड़ वाणिज्यिक बैंक। उपरोक्त आंकडे कृषि ऋण के सर्वग्राही मकड़जाल के विस्तार के धोतक है। 70 प्रतिशत कृषि भूमि है छोटे (1–2 हैक्टेयर वाले) एवं सीमांत (1 हैक्टेयर से कम वाले) किसानों के पास 35 प्रतिशत हिस्सा ही मिल पाता है छोटे और सीमान्त किसानों को कुल कर्ज आवंटन का। केवल 26 प्रतिशत किसानों को ही फसली ऋण मिल पाता है। 25 प्रतिशत कर्ज साहूकारों और अन्य सूदखोरों के मार्फत लिया जाता है।

मुल्क के किसानों की समस्या केवल बैंकों से लिया जाने वाला कर्ज ही नहीं हैं। मुल्क भर में साहूकारों का जाल अब भी फैला हुआ है, जो गरीब किसानों की मजबूरी का लाभ उठाकर उनकी जमीन, गहने आदि गिरवी रखवाकर ऋण देते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के चंगुल में किसान फंसे रहते हैं। ऐसे मजबूर किसानों को कर्जमाफी का कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनकी पहुंच बैंक तक होती ही नहीं।

किसानों के आत्महत्या के प्रमुख कारणों में एक बड़ी वजह कर्ज का बोझ और दीवालियापन है। किसान आर्थिक संकट से ऊबर नहीं पा रहे हैं। किवंदंति है कि किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मरता है। फसल बोने के लिये लिया कर्ज कोढ़ में खाज का काम करता है। एक बार कर्ज माफी के बाद किसान को फिर नए सिरे से कर्ज माफी की दरकार होती है। यानी कर्ज और कर्ज माफी दोनों ही स्थायी समाधान नहीं, बल्कि फौरी राहत भर है। 'नेशनल सैंपल सर्वे' के 'सिचुएशनैल असेसमेंट सर्वे' के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसान परिवारों की औसत आय चार हजार नौ सौ तेइस रुपये है और उसका खर्च छह हजार दो सौ तीन रुपये है। इस सर्वे के नतीजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार को हर महीने तेरह सौ सात रुपये यानी सालभर में पंद्रह हजार छह सौ चौरासी रुपये का अतिरिक्त जुगाड़ करना पड़ता है। पैसों का यह अतिरिक्त जुगाड़ बैंकों से कर्ज से नहीं हो पाता है, बल्कि ऊंची ब्याज दर पर स्थानीय साहूकारों से लेना पड़ता है। साल दर साल किसान के परिवार पर यह कर्ज बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्याज चुकाने में ही उसका दम निकल जाता है।

आज देश में किसानों के हाल बद से बदतर हो रहे हैं। सूखा, फसलो का चौपट होना और कर्ज में डूबने के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। वर्ष 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 56 फीसदी देश के कामगार खेती से जुड़े है। लेकिन खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है। भारत में खेती, खेती के आकार अनुपात में कम उत्पादन तथा विपणन के अभाव का सामना कर रही है। कृषि का जीड़ीपी में केवल 17 प्रतिशत हिस्सा है। 6426 रुपये है। औसत काश्तकार की आय और 6423 रुपये खर्चा। यह मुल्क की त्रसदी ही है कि जो किसान पूरे मुल्क का अन्नदाता है वह आज भिखारियों की तरह सरकार से कर्ज माफी की मांग करता फिर रहा है। हर साल हजारों किसान आतमहत्या कर रहे हैं, और लाखों किसान अपना घर बार छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार में सरकार में आने पर कृषि उपजों के लिए 'स्वामीनाथन कृषि कमीशन' की अनुशंषा के अनुसार, लागत पर कम से कम पचास फीसदी लाभ देने का वचन दिया था लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले तो किसान की भूमि बैंकों को गिरवी नहीं रहेगी एवं किसान ऋणमुक्त हो पाएगा। यक्ष प्रश्न है कि क्या किसान के 'अच्छे दिन' आएंगे ?

किसान का दर्द ना समझा कोई

– सोमपाल शास्त्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री

महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश किसानों का यह आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ। यदि अतीत के पन्ने पलटें तो दो–चार साल के अंतराल में इस तरह आंदोलन होते रहे हैं। जब किसानों की पीड़ा असहनीय हो जाती है तो वह इस दिशा में कदम उठाने को मजबूर होते हैं। हांलाकि, इस तरह के आंदोलन में हिंसा और आगजनी को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता लेकिन सरकार को यह जरुर सोचना चाहिए आखिर इस तरह के हालात पैदा ही क्यों हुए, इस आंदोलन के खड़े होने की वजह क्या है ? हकीकत यह है कि किसी भी किसान के पास इतना फालतू समय नहीं होता कि वह अपने कामकाज को छोड़कर सड़क पर उतर जाए।

दरअसल, हमारी कृषि व्यवस्था में ऐसी आधारभूत खामियां है, जिससे यह संकट बार–बार सामने आ जाता है। सरकार इसका तर्कपूर्ण और दीर्घकालिक समाधान तलाशने के बजाय आग पर काबू पाने के लिए ऐन वक्त पर कुंआ खोदने सरीखा उपाय करती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी मूल वजह को दरकिनार करने की कोशिश की गई है। इस बार किसानों के आक्रोशित होने का यही प्रमुख कारण है। फिलहाल आंदोलित किसान जो मांग उठा रहे हैं उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

धैर्य रखना मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। –ससो

में वृद्धि, मंडी व्यवस्था में सुधार, एमएसपी पर उपज की खरीद सुनिश्चित करने और कर्ज माफी की मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनमें पहली तीन तरह से जायज हैं जबकि कर्ज माफी का बीज सरकार ने खुद बोया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भाजपा ने किसानों का कर्ज माफ करने का खूब ढिंढोरा पीटा था। बेशक आधा–अधूरा ही सही लेकिन सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण माफी ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर अन्य राज्यों के किसान द्वारा भी यह मांग मजबूती के साथ उठाई जा रही है जो अब उग्र रूप धारण कर चुकी है।

यदि किसानों के शोषण की बात की जाए तो ब्रिटिश काल से ही होता आ रहा है। अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक किसानों का अपने मनमाफिक शोषण किया। इसके कई प्रमुख उद्देश्य थे। दरअसल, संगठित मजदूर और मुख्य शहरी जनता अनाज के दाम बढ़ने पर आक्रोशित होती है। उन्हें शांत रखने के लिए अनाज के दाम सस्ते रखे गए। उस दौरान वास्तु विनियम के लिए अनाज का ही इस्तेमाल किया जाता था। तब मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। मजदूर अथवा वेतन के रूप में अनाज देने की व्यवस्था थी। यदि खाद्यान्न महंगा होता तो ज्यादा मजदूरी की मांग उठती। अतः अपने निहित स्वार्थ के लिए अंग्रेजों ने अनाज के दाम बढ़ने नहीं दिए।

देश में आजादी के बाद किसानों में उम्मीद जागी कि अब स्थिति में बदलाव होगा लेकिन यह हालात लम्बे समय तक जारी रहे। आलम यह है कि भारत सरकार ने पहली बार 1965 में कृषि मूल्य बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति लागू करने पर विचार किया। शुरूआत में यह व्यवस्था सिर्फ गेहूं और ध ाान के लिए ही की गई। इसके तहत यदि इन जिंसों के भाव बाजार मूल्य से नीचे जाते हैं तों उसकी खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी। इस लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) की स्थापना की गई। इसके बाद गेहूं और धान की पैदावार में अच्छा–खासा इजाफा देखा गया। वर्ष 1986 में देश में गन्ने की बंपर फसल हुई लेकिन उसके लिए कोई खरीदार नहीं था।

इस संबंध में मैने किसानों के एक दल के साथ तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह से मुलाकात कर सुझाव दिया कि जब दुनियां के कई देशों एमएसपी पर सारी कृषि जिंसों को खरीदने की व्यवस्था है तो यह भारत में क्यों नहीं हो सकता। उनके प्रयासों से तब 20 कृषि जिस 'एमएसपी' के दायरे में आ गई। फिलहाल सरकार कृषि लागत आधार पर 24 जिंसों का एसएमपी तय करती विंढम्बना यह है कि आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान के अलावा और किसी फसल के खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई है।

यह व्यवस्था भी सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। बाकी राज्यों में किसानों को मडियों में आनन फानन औने–पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है जबकि वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में भाजपा ने 'स्वामीनाथन रिपोर्ट' लागू करने का लिखित में वादा किया था। इसके तहत आयोग कृषि मूल्य एवं फसल की लागत का जो अनुमान लगा उसमें 50 फीसद लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाएगा। सरकार ने एक साल पूरा होने पर इस वादे पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस बारे में सरकार ने लिखित जवाब में कहा है कि इस वादे को पूरा कर पाना संभव नहीं है। 'स्वामीनाथन' का दूसरा सुझाव है कि किसानों को चार फीसदी ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए जो विभिन्न शर्तों के साथ किसान छोटी अवधि ा के लिए ही दिया जा रहा है। सरकार ने अपने लिखित वादे पर भी अमल नहीं किया। ऐसे में किसानों को आक्रमण फूटना जायज हैं। विडंबना यह है कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के बड़े–बड़े दावे कर रही है । धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।

हकीकत यह है कि आज आलू, प्याज, बासमती, टमाटर और गोभी के भाव 2013 के स्तर से नीचे आ गए हैं जबकि लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इस बारे में मैने पांच माह पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक में उन्हें आगाह किया था कि जब किसानों का दर्द नहीं समझेंगे तब तक उनका भला नहीं होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि विनिर्मित उत्पादों की 46 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र की कृषि आय पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र की शक्ति कम होने पर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे बेरोजगारी की फौज बढ़ेगी। ऐसे में सरकार को कृषि ऋण माफी जैसे फैसले लेने के बजाय किसानों की वास्तविक आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं। यदि किसानों का सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा तो आगे चलकर पूरे देश को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

भारतीय किसान पार्टी के गठन की प्रभातवेला

– सूरजभान दहिया

भारत एक कृषि प्रधान देश है और रहेगा भी। कृषि भारतीय सभ्यता की आत्मा है, इसलिए हमारे संस्कार कृषि के ईद–गिर्द ही घूमते हैं। अपनी संस्कृति को संजीव बनाये रखने के लिए हमारा प्रथम दायित्व यही हैं कि हम अपने साधन (कृषि) और साधक (किसान) के प्रति समर्पित रहे। हमारे कई हजार साल के इतिहास में ऐसे कई रोमांचक प्रसंग हैं जब फसल न हो जाने पर राजा ने तपस्या की अथवा स्वयं ही हल उठाया। अब कुछ अजीब सा हो रहा है, दिनोदिन कृषि संकट गहराता जा रहा है पर शासक व प्रशासन किसान के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद सिर्फ एक बार सन् 1965 में पूरे देश ने 'अनाज में आत्म निर्भरता और अन्नदाता किसान' का महत्व पूरी गहराई से अपने दिल और दिमाग में रेखाकिंत किया था। लाल बहादुर शास्त्री के आहवान पर पूरा देश

ही किसान बन गया था, शास्त्री के अन्तःकरण से दिल्ली के रामलीला ग्राऊंड़ में, एक उद्घोष हुआ– 'जय जवान, जय किसान'। यह उद्घोष जनजन तक पहुंचा और अनाज निर्यातक अमरीका की घौंस धरी की धरी रह गई। उसके राजदूत ने अपनी सरकार को रपट भेजी थी कि भारत में इन दिनों जैसी प्रबल भावना है, यदि यह बनी रही तो इस क्षेत्र में अमरीका के हित खतरे में पड़ सकते हैं। शास्त्री जी ने एक्टर मनोज कुमार को बुलाकर कहा – "मनोज। देश के किसान की कृतज्ञता को आप सिनेमा के माध्यम से राष्ट्र के सामने रखों। फिल्म 'उपकार' बनी और एक सन्देश भारतीयों के पास पहुंचा – "अन्न के मामले में किसान का देश को आत्म निर्भर बनाने का पवित्र दृढ़ सकंल्प।"

भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति का किसान ने सूत्रपात किया और भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होने का गौरव दिला दिया। परन्तु यह कैसी विडंबना है कि किसी भी राष्ट्रीय समारोह में यह आभाष नहीं होता कि हम किसान संस्कृति के पालक हैं। हमारी संस्कृति कृषि से जरूर उपजी है परन्तु कृषि हमारी प्राथमिकताओं से गायब है। अन्नदाता किसान अपनी आर्थिक तंगी के कारण आत्म हत्या का रास्ता अपनायें, यह भारत की इस सदी की सबसे बड़ी त्रास्दी है। किसान चम्पारण सत्याग्रह जिसके द्वारा मोहनदास कर्मचन्द गांधी 'महात्मा' बने का यह शताब्दी वर्ष है। इस लिये कृषि प्रधान भारत में लोकतन्त्र को एक नई आवाज भारतीय किसान पार्टी का अस्तित्व में आना सामायिक है। सूखा, भूखमरी, ज्वलंतमुद्दे इस पार्टी के गठन हेतू जमीन तैयार कर चुके हैं, बस सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है।

जो इतिहास को भूला देते हैं, वे इतिहास नही रच सकते हैं। भारत में जब–जब परिवर्तन का बिगूल बजा है उसके नायक सदैव किसान रहे हैं। दुःख इस बात का है कि आजाद भारत में किसान इतिहास को दफना दिया गया। अभी–अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि हमारे समाचार पत्र सिर्फ 4 प्रतिशत कवरेज कृषि को देते हैं और 2 प्रतिशत ग्रामीण परिवेश को। हमें क्यों 60–70 करोड़ किसानों की आवाज सुनाई नहीं देती, क्यों लोकतन्त्र में इतने बड़े समुदाय को राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक हैं। हम लोकतंत्र हैं, 'वोट हमारे राजतुम्हारा यह घोर अन्याय है, यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के नाम यह माननीय मूल्यों को हनन है, अब यह षड़यन्त्र आगे नहीं चलने वाला।

उपरोक्त षड़यन्त्र को गम्भीरता से समझना चाहियें। हमारे गणतंत्र स्वाधिन होने का संघर्ष 1857 से शुरू होता है। वैसे हमारे गांव तो 'लघुगणतंत्र' थे ही जहां राजा नहीं जन शासक होता था। यह व्यवस्था चौपाल में बैठकर सब की सहमति से संचालित होती थी और इन्हीं से एक प्रभावी खाप परम्परा बनी। अंग्रेजों के शोषण के विरूद्ध खापों ने जगह–जगह विचार विमर्श करके 1857 में एक जनआन्दोलन चलाकर अपनी नियती के स्वयं निर्धारण करने का निर्णय लिया। हल उठे, 1857 के स्वतंत्रता संग्रम का बिगूलबजा, लालकिले पर खाप परम्परा परिभाषित हुई – "खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, अमन अवाम का" विश्व इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध आज तक का यह सबसे बड़ा और अतिशक्तिशाली किसान संघर्ष स्वीकारा जा रहा है। इस संग्राम में भारत की कुल जनसंख्या के 7 प्रतिशत जन ने अपने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर किये। यद्यपि ब्रिटिश हुकुमत की बड़ी ताकत और अनेक देशी रियासतों, दलालों व चाटूकारो की साजिश के आगे भले ही उस वक्त यह अपनी मंजिल तक नहीं पहुचा लेकिन कठिन और प्रतिकूल प्रस्थितियों के बावजूद यहां के किसान क्रांतिकारियों ने देश में स्वाधिनता, राष्ट्रीय और जातीय एकता की एक ऐसी मशालजलादी, जो बाद के संघर्षों का लगातार मार्गदर्शन करती रही। आश्चर्य है कि इस इतिहास को पाठ्यक्रमों क्यों औझल कर दिया, समझ नहीं आता।

अंग्रेजो को किसान शक्ति का इस संग्रम से अहसास हुआ और उन्होंने अनेक हथकंड़े अपनाकर किसान की कमरतोड़ दी। किसान के गणतंत्र गांवों की काश्तकारी और दस्तकारी को अंग्रेजो ने तहस नहस कर डाला। किसान को इस संकट से निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई न रहा था। बींसवी सदीं के आरम्भ में उत्तरी भारत में एक अलौकिक शक्ति किसानों के बीच चौ० छोटूराम के रूप में आई। 75 साल से पीस रहे किसान की पीड़ा को उन्होंने एक जेहाद के रूप में राजनीतिक, मीडिया व प्रशासन के पटल पर रखा। इसके द्वारा किसान ने भी सुस्ती तोड़ी, अंगडाई ली और चौ० छोटूराम के साथ खड़े हो गये। किसान को नरक की जिदंगी से निकालने के लिए पहले कांग्रेस को राजनीतिक मंच को उन्होंने तलाशा, अंग्रेजो के काले कानूनों को उन्होंने चुनौती देकर ब्रिटिश सरकार को ललकारा व सेठ साहूकारों के कर्जो के हाथों को तोड़ने का बिड़ा उठाया। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे अंग्रेज अफसर हो, चाहे सूदखोर हो सभी तो चौ० छोटूराम के कट्टर विरोधी हो गये। चौ० छोटूराम अकेले पड़ गये, पर अविचलित रहे। उन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आंधियों, तूफानों व ज्वारभाटा को ललकार और किसान शोषण मुक्ति की एक संघर्षपूर्ण इबारत लिखदी जिसमें वैचारिक गहनता, स्पष्टता, मानवता और प्रगतिवादी कर्मठता थी। सन् 1923 में उन्होंने एक नई राजनीति को परिभाषित किया – किसानों की राजनीति। इस राजनीति को साफ मतलब था कि जिनके हक मारे गए हैं, उन्हें उससे मुक्त कराया जाए तथा नवजीवनीय मूल्यों के प्रति उनमें आस्था जागृत की जाए। फजले हुसैन के साथ मिलकर चौ० छोटूराम ने पंजाब मं उपरोक्त विचारधारा को लेकर एक नई राजनैतिक पार्टी – राष्ट्रीय यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। यह एक किसान हितैषी पार्टी थी, इसलिए यह जमीदारा पार्टी के नाम से ही लोकप्रिय हुई।

जमीदारा पार्टी का गठन जीतग्रस्त मानसिकता से परे और धर्म उन्माद से ऊपर रोजी, रोटी की लड़ाई के लिए एक साहसिक राजनैतिक नया प्रयोग था जो गहन सोच की दार्शनिकता पर शोषक और शाषित का द्वन्द्व था। उसने थोड़े ही समय में पंजाब की आर्थिक राजनैतिक, शैक्षणिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कांग्रेस व मुस्लिम लींग जैसी राष्ट्रीय पार्टी इस पार्टी के सामने पंजाब का अपना वजूद खो बैठा। कायदे आजम जिन्नाह व पंडित जवाहर लाल नेहरू चौधरी छोटूराम के सामने पंजाब में असहाय दीखें। 1935 के एक्ट के अनुसार पंजाब एसेम्बली के चुनाव 1937 में हुये जमीदारा पार्टी को 175 सीटों में से 101 सीट मिली, कांग्रेस को 20, गैर जमीदा हिन्दु पार्टी को 15 तथा मुस्लिम लींग को सिर्फ 2 सीटें मिली। जमीदारापार्टी की पंजाब सरकार बनी तथा चौधरी छोटूराम ने चन्द वर्षों में 30–40 कानून बनाकर पंजाब में

किसानों को कर्जों से मुक्त करा दिया, गिरवी रखी भूमि किसानों को वापिस मिली, किसानों को उन्नत खेती करने को प्रोत्साहित किया तथा गांधी जी के रामराज्य के सपने को आगे बढ़ाया।

पंजाब के किसान ने नये सूरज को उगते देखा और वह अनायस बसन्त पंचमी महोत्सव पर झूम उठा। विरोधी पार्टियों ने चौ० छोटूराम पर तीखे प्रहार करते हुये यह सरकार पंजाब की सरकार नही है परन्तु जमीदारों की सरकार है। चौ० छोटूराम ने संघर्ष विरोधियों की दलीलों को स्वीकारा और कहा 'आज बेशक पंजाब में किसानो की सरकार है कल भारत में भी किसान राज करेगा।' इतिहास के समीक्षक अब लिखते हैं :– बींसवी सदी का पूर्वाध विश्व की तीन महानक्रातियों का युग था और तीनों क्रातियां किसान से सम्बन्धित थी – रूस क्रांति, चीन क्रांति और पंजाब क्रांति। पहली दो क्रांतियां में अपार रक्त बहा लेकिन और माओं विश्वख्याति पा गये, चौ० छोटूराम की मुक्ति क्रांति रक्तहीन थी और दोनों क्रांतियों से कहीं अधिक कारगार रही। आश्चर्य होता है कि इस क्रांति की उपलब्धियों को भावी पीढ़ी की जानकारी हेतु ओझल क्या रखा है ? क्यों चौ० छोटूराम के व्यक्तित्व को किसान हितैषी विभूतियों – गांधी जी, सरदार पटेल व तिलक की भांति पढ़ा नहीं जाता ? कदाचित शासक पार्टियां भारत में गांधी जी के हिन्दस्वराज (किसानराज) के सपने को पूरा करने से हिचकिचाती रही हैं, पर इतिहास की पुनरावृति जरूर होती है। कोई छोटूराम जरूर अवतरित होगा और पंजाब की भांति भारत में भी एक किसान पार्टी का शासन होगा।

चौ० छोटूराम 1945 में चल बसे और भारत 1947 में आजाद हुआ। इन घटनाओं ने पंजाब की जमीदारा पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। आजाद भारत में किसान संबंधित परियोजनाएं हाशिये में चली गई। किसान पर संकट के बादल गहराते चले गये, राजनीतिक पटल पर न गांधी जी थे, न पटेल और न ही चौ० छोटूराम और किसान अपने आपको अहसाय पा रहा था। चौ० चरण सिंह ने ग्रामीण भारत की समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा उठाकर किसानों की रहनुमाई का दायित्व उठाया। इस संदर्भ में चौ० चरण सिंह ने इंडिया बनाम भारत की बात रखी। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि किसान को विकास प्रक्रिया में उपेक्षित कर दिया है, इसलिए किसान आर्थिक दबाब में आ गया है, इससे राजनीतिक सवाल खड़े हो गये हैं। अनेक अर्थशास्त्रियों ने चौ० साहिब की बात में सच्चाई लगी। महाराष्ट्र में शरदजोशी ने इस ज्वलंत मुद्दा बनाया तो उत्तरी भारत में महेन्द्र सिंह टिकैत ने इसे लुटेरों और कमेरे के बीच लड़ाई कराई, अब प्रान्तीय व राष्ट्रीय स्तर किसान नेतृत्व की शून्यता है इसलिए किसान शोषण आज भी चरम सीमा पर है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां किसान हित में नही दिखती तभी तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशे नहीं क्रियान्वित हो रही है।

हमें किसान की पीड़ा को समझना होगा। किसान की आर्थिक तंगी को हमें अनुभव करना होगा। वह बेजुबान है, उसे आवाज देनी होगी राष्ट्र को बताना होगा कि कृषि प्रधान भारत में 58 फिसदी किसान क्यों भूखे सोते हैं। एक किसान परिवार की प्रतिमास आय अब ज्यादा से ज्यादा 6000 रुपये राष्ट्रीय सैम्पल द्वारा अनुमानित की गई है जब कि एक सरकारी मुलाजिम की सातवें वेतन आयोग के बाद कम से कम 18000 रुपये कर दी गई है ? अर्थशास्त्री मानते हैं कि आजादी के बाद किसान ने भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, भीषण वर्षा व भीषण सूखे को झेलकर भी गेंहू का उत्पाद सातगुना, मक्का चार गुना और चावल का तिगुना कर दिया इसके बावजूद किसान क्यों नरक की जिंदगी बिता रहा है ? आज सामान्य किसान और खेतीहर मजदूर की झोपड़ी में न लक्ष्मी (समृद्धि) और न सरस्वती (शिक्षा) है, बेकरारी उसके दरवाजे पर निरंतर दस्तक दे रही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न मन में बार–बार उठता है कि हरित क्रांति (अनाज में निर्भरता) श्वेत क्रांति (दूध में आत्म निर्भरता) और नीली क्रांति (मछली पालन में निर्भरता) का अमृत कुंभ कौन ले भागा है ? कहां और क्यों अंटकगई – ग्राम विकास की हरहराती गंगा ?

देश में अभी तक किसान समृद्धि नीति नहीं बनी है। यहां कृषि नीति जो भी बनी है वह प्रायः औद्योगिक हितों की मातहनी करने के उद्देश्य से ही सूत्रवहद की गई। गांधी के बताये गए उपायों द्वारा प्रत्येक ग्राम को स्वावलम्बी ईकाई बनाने का प्रयास किया जाना था, जो नहीं हुआ। ग्राम रोजगार पर काफी जोर दिया जा रहा था, उल्टा हुआ। शहरीकरण पर जोर दिया गया, अब भी दिया जा रहा है। शहर की तरफ पलायन हवसकारी हैं इसलिए गांव प्राचीन सभ्यता के अवशेष बन गये हैं और अमीरी–गरीबी की खाई घटने की बजाय और चौड़ी होती जा रही हैं। क्या बापू के हिंद स्वराज की यही कल्पना थी ?

हमारे देश की आर्थिकनीति विदेशी शक्तियां तय करती हैं। विश्व बैंक का जोर है, भारत के 40 करोड़ ग्रामीण शहरों मं आकर बसे जो हमारी संस्कृति पर धावा है। विदेशी शक्तियां हमारी खेती को तबाह करने पर उतारू हैं। वहां की कारपोरेट कम्पनियों को पता है कि भारत की रीढ़ किसान है, उसे नष्ट कर दो, भारत आर्थिक गुलामी स्वतः दस्तक दे देगी। विर्दभ में संतरा 3 रुपये किलो खरीदा जाता है। महाराष्ट्र से प्याज भी 3 रुपये किलो खरीदा जाता है, पंजाब से आलु एक रुपये प्रति किलो लिया जाता है। कभी–कभी तो किसान सड़क पर बोर्ड लगा देता है तो टमाटर व प्याज 100–100 रुपये प्रति किलो बाजार में बिकता है। । उधर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि किसान पर इन्कमटैक्स लगाना चाहिये – किसान मालामाल है, फूड सब्सीडी खत्म होनी चाहिए। न्यूनतम कृषि समर्थन व मूल्य प्रक्रिया बंद होनी चाहिये, समझने की बात तो यह है कि किसान को आर्थिक हक क्यों नही मिलता ? जरा सोचिये, 1970 में गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल था और 2016 में यह 1525 रुपये – कितना मालामाल हो गया किसान इससे ? और तथ्यों का भी अवलोकन कीजिए – 2004 से 2015 तक कारपोरेट जगत को भारत सरकार ने 42 लाख करोड़ रुपये की राहत दी जबकि किसान सब्सिडी इसी दौरान सिर्फ 2 लाख करोड़ की थी। किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत कहा करते थे "हमारे देश में पूंजीपति सत्ता से रिश्ता जोड़कर किसानों का लहू चूसते हैं। अपने हाड़–मांस गला कर खेती करने वाला किसान तो हमेशा सूने आकाश की ओर ताका करता हैं।"

आज कृषि क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन लाने की अनिवार्यता है। जिससे प्रत्येक किसान का रहन सहन एक अपरिहार्य न्यूनतम है यह क्या माजरा है कि सरसो उगाने वाला किसान भूख से मर जाता है जबकि सरसों से तेल निकालने वाला मिल मालिक चन्द वर्षों में ही

अहंकार से तप नष्ट हो जाता है और इधर–उधर कहने से दान निष्फल हो जाता है। –मनु

करोड़पति हो जाता है नीति बन जिससे प्रत्येक किसान का रहन–सहन एक अपरिहार्य न्यनतम स्तर प्राप्त कर सके, कृषि को सम्मानित व्यवसाय का रूप मिले तथा देश कर विकास की भावी दिशाये गांव व खेत–खलियान द्वारा तय हो। भारत में कृषि राष्ट्रीय जीवन और अर्थ–व्यवस्था का मूलभूत आधार रहें। इसके लिये यह अब जरूरी हो गया है कि देश के 60–70 करोड़ किसान अपनी नियति का स्वयं निर्धारण करें और अपनी आवाज एक मंच पर आकर अपनी राजनीतिक शक्ति का परिचय दें। मानते हैं कि इतिहास दोहराता है। याद करे आज से कोई सौ साल पहले 923 में जब चौ० छोटूराम ने जमीदारा पार्टी बनाई थी तो उन्होंने उद्घोषणा की थी – "यह पार्टी उस ग्रामीण शक्ति को परिभाषित करती है जिसे अब अवसर मिलेगा और वह कर्म एव लग्न से नव पंजाब की इबादत लिखेगी।" एक दशक में ही चौ० छोटूराम ने पंजाब में इस पार्टी की सरकार बनवा दी और उन्होंने अपने ग्रामीण भाईयों को यह कहना आरम्भ कर दिया कि "अब तो तुम्हें अभियान होना चाहिये कि पंजाब में तुम्हारी सरकार है। यह तुम्हारे हित के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, तुमने ही उसे बनाया है और तुम से तुम्हारे ही भाई उसे चला रहे हैं। पंजाब में अब सुनहरी युग की वेला है – इतिहास इसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा।"

लोकतंत्र में जनशक्ति होती है अतएव सम्पूर्ण भारत में सुनहरी युग लाने के लिए किसान अपनी जमीदारा पार्टी पुनः गठित करके किसान मसीहा चौ० छोटूराम को सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करके गौरवान्वित हों। भारत में खेती, किसान और ग्राम विकास की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, अब किसानों में भी समृद्धि आनी चाहियें। गांव और शहर को लेकर आर्थिक मोर्चों पर एक लड़ाई है। बहुसख्यंक जनता जो गांव में निवास करती है मूलभूत सुविधाएं उसे भी मिलनी चाहियें वरना गांव उजड़ते जायेंगे तथा सब कुछ शहरों में समा जायेगा। अतएव गांवों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होनी जरूरी है। जिन समूहों–समुदायों–वर्गों–तबको के पास वोट की ताकत हैं वे अपने अधिकार मागेंगे ही अतः जमीदारा पार्टी का गठन होना है, सामयिक है – यही लोकतंत्र की खूबी है – वोट जिसके, सरकार भी उसकी।

Transforming this India into a New Resurgent India - and Waging War against Poverty

(1. Four keys to open the doors of prosperity of a developing county are population control, Infrastructure development, reforms and total sanitation-India is lacking in all the four.)

(2. India is standing at the precipice of the socio-economic rock. If the problem of population explosion is not solved urgently, the country will fall into the abyss of disaster. Even UNO has warned that population of India will be surpassing that of China by 2024.)

(3. There are not enough people in India who are really worried about her bleak future and poor standing in the comity of nations.)

To,

Dated:-16-07-2017

Shri Narendra Modi,
Honorable Prime Minister of India
New Delhi.

Sub:-Transforming This India Into a New Resurgent India

Respected Sir,

With utmost respect at my command, may I say that I am writing this letter because you have invited constructive suggestions from the listeners of your regular "Mann Ki Baat" program. I do not belong to any political party. I am a rationalist and nationalist to the core. Constant pain in my heart is of India not surpassing China in the economic race though India is endowed with more natural resources and was ahead of China till 1976. Leaving aside every issue, I look at the present scenario purely through the prism of economic development.

Today, the Government of India is face to face with three serious problems i.e. rising population or demographic disaster, dehumanizing poverty and increasing unemployment among youth. Indian populationwas 122 crore in 2011. Since then, we are adding one Australia (18 million people) every year. India will be beating China in the population race in 2024 and she may cross 150 crore mark by 2030. Population of this size will create quick sand conditions and become thoroughly unmanageable. All economic models will fail to operate leading to both social and financial anarchy in the country.

Poverty is a curse and the blackest spot on the fair name of the country. 26% (34 crore) people are still wallowing in tear jerking poverty called BPL families. An equal number are surviving just above the poverty line. They are called marginally poor. Their total number is more than the combined population of US & Europe. Poverty alleviation programs only allow them to subsist and do not release them from the vice like grip of poverty. Therefore, the govt needs to wage a total war (blitzkrieg) against poverty. This war has not started yet.

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। –रवीन्द्रनाथ टैगोर

7% GDP growth (now 6.1%) is putative and jobless.(GDP growth is not the sole indicator of overall development of the country.Other equally important indicators are Human Development Index, Ease of Doing Business and number of families living below the poverty line India occupies 130th place in the World Bank Table in respect of these factors. HoweverGST bill, a great economic reform will up the ante to sum extent after 6 months. Accordingly, mood of the people is one that of despondency. Your political stars are definitely inascendance but the goodwill reservoir created in 2013-14 has started evaporating day by day.People want you to succeed and come with flying colors because there is complete famine of game changers in other parties and this is the last chance to convert demographic disaster into dividend. To achieve this objective you will have to incarnate statesmen like – Sardar Patel, Deng Xio Ping or Lee Kuan Yiew.

One single indicator of development is the availability of large number of vacancies for Engineers, MBAs and other categories in weekly employment supplements in leading newspapers. But presently we find some vacancies for teaching staff only. The common man in the villages is lamenting for 2 things i.e. regular supply for irrigation water and prevention of loot by private hospitals and schools. World Bank says, "One part of Indian Poverty is due to poor service delivery from existing infrastructure," Industry is now facing severe recession. Progress in water resources and hydro power development is notional. The population bomb can explode anytime as we are adding one Australia every year.

Besides this, the overall economic health of the county is not sound. Sensex is wobbling because of FIIs and the bubble may burst any time. Exports are not increasing. The entire demonetization experiment also did not cut much ice as generation of black money has restarted. The debt on all the States is more than Rs.40 lakh crore and the figure is rising every year. The debt on Maharashtra statealoneisRs. 4.25 lakh crore. Same is the fate of power utilities in States. Air India is buried under a debt of Rs. 50,000 crore. Good fortune is that the price of crude oil is still stabilized at $52 per barrel.I agree that these problems were inherited from the UPA regime but were not addressedfully bythis government as well.

The real frustrating concern before the youth is the high wall of unemployment. Four lac Engineers and MBAs are passing out degrees every year. In other words, the future of vast army of Indian youths is at stake. This high wall can be scaled only by heavy and fast investment in developing solar energy, core infrastructure projects, dairy development and horticulture projects in 7N-E states, filling of large number of existing vacancies and establishing 30 new cities to act as sub-capitals in states.One fails to understand what your advisors are doing?

Now you have floated a new idea of building "a culturally strong, socially vibrant and economically buoyant New India" by 2022. The idea is wonderful but the period of 5 years is too less for its embellishment. Moreover, you have not explained the details how this dream will be fulfilled by 2022. India will be deemed culturally strong, socially vibrant and economically buoyant if following targets are met in a time bound manner. It will still be a miracle if these milestones are crossed by 2030.

a) To beat China in economic race.
b) Complete eradication of poverty.
c) Removal of tag of India being an under-developed country even 70 years after independence.
d) Enough employment opportunities for the vast army of unemployed youths.

These milestones are needed because Indian independence is now 70 years old whereas countries like Germany & Poland who were virtually decimated during second world war were able to rebuild their economies within 15 years and are now a force to reckon with. Why not India? Because there is no fire in our bellies.

Now I give below a 22 – point program which if implemented at war footing efficiency, can transform present India into a New India of your dreams-:

1) Govt should frame a proper strategy of plucking the lowest hanging fruits (development of solar energy) which can transform the Indian economy in no time and open the flood- gates of employment opportunities. India can become the greatest solar power and leader in the world within two years by resortingto solar water heating, solar cooking and roof top solar power on a massive scale.

2) The Govt. should be bold enough to split 6country size states into smaller ones. It will be the biggest administrative reform of the century. Poverty in these states will go only after these are subdivided into smaller states.

3) The government should launch a new program of constructing Express-waysconnecting ports with hinter land. A new modern sea-port needs to be located near Surat. Following Express-ways need to be the constructed very soon.

a) Amritsar to Kandla
b) Delhi to Kolkata
c) Allahabad to Surat
d) Patna to Paradeep

4) The Progress in respect of development of water resources and hydropower is also negligible. The main cause of suicides of farmers in central India is the lack of irrigation facilities. The backbone of Indian economy is agriculture and the backbone of agriculture is regular irrigation water supplies. Therefore, govt should launch a massive program of water harvesting in case of river valleys where rainfall run-off is flowing to the sea unutilized. For example, valuable run-off of river Yamuna flows to the sea causing floods in the way during rainy season every year whereas farmers of Haryana are facing grave water crisis. This is happening because storage dams were not

built across the river and its tributaries. Likewise, a massive program of developing 50,000 MW of hydro power in 6 hill states should be re-launched. This program was launched in the time of Vajpayee Ji but abandoned without any reason. River Brahmaputra alone can generate 70000/-MW of hydro power with 100% power load factor.

5) The Govt. should launch an ambitious program of developing 7 N-E-States as hub of dairy development and horticulture.This single step will bring milk and food revolution in the Country. These states have not yet fully mingled in the national mainstream.

6) Indian Railways (IR) has a tremendous scope to become an engine of growth. But it is struggling below poverty line because the govt does not have the guts to raise the fares. Passenger trains are virtually providing free ride. The government should urgently allow States to run trains in their respective beats. This single step will revolutionize Indian Railways. A program of providing missing links in railway network (3000km in all) and running more trains on grossly under-utilized tracks should be launched simultaneously. For example, only one train runs on Rs. 600 crore Sonipat – Jind railway track.

7) Modern technology parks like IMT Manesar and SEZs were not setup along the coastal areas to help the foreigners to set up their factories.POSCO is still sitting idle for the last 12 years and has not been allotted land to set up a huge Iron Plant.

8) The Prime Minister should captain the team of Chief Ministers to involve them fully in the development of important projects. They treat the states as their personal fiefs. This is another important reason for the slow progress of the country. The administration in Haryana is thoroughly paralyzed because of large number of vacant posts. There is no way to punish a laggard State Government.

9) The Government should work hard to improve the Human Development Index (HDI) and Ease of Doing Business. Both parameters lie at 130th place in a list of 190 countries.

10) The Swachh Bharat Abhiyan should include the program for total sanitation (100% sewerage and solid waste management, sweeping, paving of surface along the road edge) and not limited to constructing house hold latrines only. It should be pursued with great passion.

11) Thirty new towns be setup to act as sub-capitals of various states. These new towns will provide the maximum scope for employment.

12) Six hill states should be redeveloped as new Switzerlands by improving road conditions, tourist hot-spots and reducing distances between cities by constructing road tunnels.

13) China is executing lot of projects in Africa. India should follow this example.

14) Health services in Government hospitals are almost paralyzed and need urgent improvement. A vigorous program for preventive healthcare needs to be initiated in right earnest.

15) Quality of Engineering and medical education in private institutions has touched a new low. Something needs to be done to arrest this trend.

16) Freshеffortsbe made to reframe the two retrograde bills i.e. amended Land Acquisition Act and Food Security Bill. Even well-to-do people are getting wheat and rice at Rs. 2/kg.

17)

a) Special effort be made to develop a wide industrial base for defense production so that import of defense equipments is reduced to the minimum and a huge amount of foreign exchange is saved.

b) Manufacturing of electric cars should be given a very big boost to solve the problem of air pollution in cities.

18) Progress in exploring and developing new hydrocarbon resources is very slow. A well-defined strategy should be framed to improve the existing exploratory program (NLEP) and new target should be set to explore and develop more hydro-carbons. Rajasthan area has great potential and needs aggressive investigation.

19) India should setup some world class research institutions in the field of Science and Technology. Special care should be taken to stop brain-drain. Large number of students passing IITs& IIMs serve in foreign countries and India has to do with mediocre. Govt should launch a special program to stop the practice of granting phony PhD degrees.

20) Strong measures need to be taken to bring states under strong financial discipline. Presently the debt on States is more than Rs. 40 lakh crore and the amount is rising every year. One state took loan from a bank to pay the installments of other banks. Another state took loan of Rs. 1500 crore to pay the salaries of the staff. The financial health of power utilities in most of the states is critical. Now a new wave of waving loans of farmers is developing to dry up the treasuries of the States. Cries of implementation of Swaminathan report (promised by BJP in election manifesto) are also audible at a very high pitch. So, financial mess created by states due to freebies and misuse of funds is as serious as the problem of population explosion.

21) A massive program should be taken up aggressively to prevent adulteration in food items.

22) Finally, there is absolutely no effort to control the bludgeoning population. Previous govts are equally to blame for this casual approach. We are adding one Australia to the National pool every year. Population growth at this rate is the most potential threat to the social stability of India as it will bring total anarchy and cause implosion in the country by 2030 when all development models will fail to operate.Now even UNO has warned that population of India will be surpassing that of China by 2024. So, we are standing at the precipice and this is last chance of survival of India against the impending socio-economic disaster. Therefore, time has arrived to introduce one child policy by

adopting innovative approach for creating public awareness. (Population of India in 2017 = 134 crore, 2024 = 144 crore)

Only NHAI is showing progress at the desired pace. I wish all other projects are executed at the same speed. Prime Minister of a county is the second God and Chief Ministers are the demi – Gods because the destinies of 1250 million people are tied in the grips of their hands.

God has given a wonderful opportunity to your good self to serve this country with aplomb and beat China in the economic race by 2030. This opportunity should not be lost (like Dr. Manmohan Singh) at all.It is hoped that Your Good-self will give full attention to my suggestions. You will be able to transform this India into a New India of your dreams by 2030 onlyif projects suggested above are initiated & executed in right earnest.Henceforth India will be passing through a long phase of critical years.

With profound regards,

Yours Sincerely,
Prof. R.N. Malik (Engineer-in-Chief-Retd.)
E-1/5 Arjun Mrg, DLF Phase-1, Gurgaon-122002
Mob:-9911078502.
Email: r.niwas_malik@yahoo.co.in

वैवाहिक विज्ञापन

- SM 4 working Jat Girl 26/5'3" BPT, MPT, CMT. Employed as Consultant Physiotheraphy in private hospital in Panchkula. Avoid Gotras: Chhikara, Dahiya, Bajar. Cont.: 09467680428
- SM4 Jat girl 24.5/5'1" B.Ed. M.A. Econimices. Business man & Politician family at Panchkula. Perferance businessman & Politician Family. Avoid Gotra: Lakra, Panwar. Cont.: 9216000072
- SM4 Jat girl (23.10.87) / 5'5" B.Com, NDA, MIS, MA Economices. Avoid Gotra : Panghal, Baloda, Bhagashra. Cont.: 9463969302
- SM 4 divorceed Jat Girl (DOB 03/1985)32.4/5'3" B.A., B.Ed., MSc. In Computer Science. Tri-City match preferred. Avoid Gotras: Hooda, Dahiya, Jatrana. Cont.: 09417467848
- SM 4 Jat Girl (DOB 02.12.91) 25.8/5'5" M.Com, B.Ed. Employed as teacher in a private school with Rs. 16000/- PM. Avoid Gotras: Kadyan, Jakhar, Malik. Cont.: 09815098264
- SM 4 Jat Girl (DOB 29.12.88) 28.7/5'3" MBBS. Employed as Medical Officer. Avoid Gotras: Dahiya, Suhag, Sangwan. Cont.: 09464952715
- SM 4 Jat Girl (DOB 21.04.88) 28.3/5'1" M.Tech from P.U. Chandigarh, GATE cleared. Avoid Gotras: Dhull, Goyat, Bhal. Cont.: 09467671451
- SM 4 Jat Girl (DOB 15.09.92)24.10/5'4" Graduate with B.Sc. I.T. Doing Job in a reputed private company in Gurgaon. Avoid Gotras: Malik, Rathi, Dahiya. Cont.: 09211121447, 09211303770
- SM 4 Jat Girl (DOB 15.08.89) B.Tech., M. A (English). Working as PGT. Avoid Gotras: Nain, Sangwan, Dhanda. Cont.: 09417196763
- SM 4 Jat Girl (DOB 14.09.88) 28.10/5'3" LLB, LLM. Pursuing Ph.D. Father ACP/Delhi Police. Avoid Gotras: Sangwan, Gahlian, Dabas. Cont.: 09810212200, 08750871193
- SM 4 working Jat Girl 24.6/5'7" B.Tech, MBA, Preference Defence Officer. Avoid Gotras: Chhikara, Chhillar, Dalal, Tomar, Shokeen. Cont.: 09313662383, 09313433046
- SM 4 Jat Girl (DOB 23.10.87) 29.8/5'5" B.Com, MBA, MIS, M.A (Economics.) Avoid Gotras: Panghal, Baloda, Bhaghasra. Cont.: 09463967847, 09463969302
- SM 4 Jat Girl(DOB 07.02.90) 26.10/5'10" B.Tech (ESE) M.Tech (ESE) from MDU Rohtak. GATE qualified. Avoid Gotras: Kadian, Rathee, Sangwan. Cont.: 08447796371
- SM 4 Jat Girl (DOB 05.12.86) 30/5'5" M.Sc. Geology, Employed as Class-I Gazzeted Officer at G.S.I. Govt. of India at Dehradun.
- Fathr School Lecturer, Mother Housewife. Avoid Gotras: Kundu, Rathee, Malik. Cont.: 08950092430
- SM 4 Jat Girl (DOB 19. 09. 91) 25.8/5'3" B.Tech. Employed in Management & Management Co. Pune. Avoid Gotras: Deswal, Malik, Rathi, Sangwan. Cont.: 08427945192
- SM 4 Jat Girl (DOB 30.06. 89) 27.10/5'4" B.Sc, BA, M.A. with History, CTET, HTET cleared, Employed in Chandigarh Police. Avoid Gotras: Gehlawat, Dahiya, Ohlan. Cont.: 08930157656
- SM 4 Jat Girl 26/5'3" Master of Philosophy, Doing job in private Hospital. Avoid Gotras: Duhan, Chhikara, Bajar. Cont.: 09467680428
- SM 4 Jat Girl (DOB19.07.90) 26.8/5'4" M.A. Sanskrit, P.Phil from P.U. Chandigarh. NET qualified, CTET, HTET cleared, Pursuing PhD from P.U. Chandigarh. Paper clered for Junior Lecturer in Haryana government. Father Government employee. Avoid Gotras: Duhan, Kundu, Sehrawat. Cont.: 09416620245, 09467632314
- SM 4 Jat Girl 26/5'5" B.D.S. Employed in Parexel Company in I.T. Park Chandigarh. Family settled at Chandigarh. Tri-city match preferred. Avoid Gotras: Kundu, Malik, Sandhu. Cont.: 09779721521
- SM 4 Jat Girl 30/5'2" B.A. Lab. Technician. Own business, Employed as Manager in Multi Coop. Society Bank at Sonepat. Family settled at Sonepat. Avoid Gotras: Saroha, Khatri, Malik. Cont.: 09466944284
- SM 4 professionally qualified manglik Jat Girl, M.A. English, Self Employed, (DOB 24.04.87) 30.1/5'1" Earning Rs. 7-8 P.A. Match preferred in tricity. Avoid Gotras: Atri, Vohara. Cont.: 09988268021
- SM 4 Jat Girl (DOB 04.08.90) 26.8/5'4.5" MCA from P.U. Chandigarh. Employed as Software Developer in MNC Industral Area Chandigarh) Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Sinhmar. Cont.: 09463330394
- SM 4 Jat Girl (DOB 29.02.92) 25.2/5'4" MSc Physics from P.U. Chandigarh. Pursuing B.Ed. Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Sinhmar. Cont.: 09463330394, 09646712812
- SM 4 Jat Girl (DOB 10.10.90) 26.6/5'8" B.Com, CA. Doing Job in a private reputed company. Family settled at Panchkula. Avoid Gotras: Thalor, Beniwal, Pachar. Cont.: 09915577587
- SM 4 (divorcee issuless) Jat Girl (DOB August, 1987) 29.8/5'6" M. Tech. in Computer Engineering. Employed as Assistant Professor in Engineering College, Landra (Pb.). Avoid Gotras: Sangroha, Lohan, Panghal. Cont.: 09464141784, 09780683938
- SM 4 Jat Girl 28/5'7" B.Tech.in Electronic & Communication. PG Diploma in wireless networking from Torento (Canada). Father retired from Haryana government, Mother housewife. Avoid Gotras: Gaglan, Savant, Dhull, Dhull. Cont.: 09211218999

किसी चीज से प्रभावित न होना ही मुक्ति है। –स्वामी विवेकानंद

- SM 4 divorced Jat Girl (DOB 11.05. 87) 29.10/5'4" PhD (Thesis submitted) MBA, UGC, NET, M.A. (Economics). Employed as Assistant Professor in a reputed College under I.P. University Delhi with Rs. 8.5 Lakh package PA. Father Professor, Government Employee. Avoid Gotras: Lohchab., Jaitain, Nandal. March preferred residing in Delhi and from Jat Community only. Cont.: 09416831895
- SM 4 Jat Girl (DOB 05.09.91) 25.3/5'6" M.Tech (CSE) Employed in a University. Avoid Gotras: Malik, Hooda, Rana. Cont.: 07696844991
- SM 4 Jat Boy (DOB 16.02.90) 27.4 /5'8" B.Tech. Mechanical. Employed in TATA Business Support Services Ltd. Mohali. Own house in Manimajra Town Chandigarh. Agriculture land and house in native village in District Hisar. Avoid Gotras: Kajla, Kaliramna, Khyalia. Cont.: 09915791810
- SM 4 Jat Boy (DOB 25.12.91) 25.6/6'2" Employed as J.E. in Corporation Panchkula. Avoid Gotras: Malik, Vigay, Rajan. Cont.: 0172-4185373
- SM 4 Jat Boy (DOB 02.05.91) 26.1/6', BA, JBT, CTET cleared, Pursuing B.Ed. Employed in IDBI Bank. Avoid Gotras: Kundu, Dahiya, Dalal. Cont.: 09888120102
- SM 4 Jat Boy 29/5'11" Employed as team leader in IT Park Chandigarh with Rs. 8 lakh package PA. Avoid Gotras: Khatri, Ohlyan, Rathee. Cont.: 09833286255, 09468463165
- PQM4 handsome Jat Boy 30/5'10" MBA (finance) from France. CFA, B.Tech (PEC). DHA level three cleared. Employed in MNC at Mumbai with good package. Family settled at Panchkula. Only son. Avoid Gotras: Mor, Gehlawat, Rathee. Cont.: 08360609162
- SM 4 Jat Boy (DOB 13.03.89) 27.8/5'10" B.Tech. M. Tech from Canada. Doing Job in Canada. PR status. Avoid Gotras: Sarao, Basiana, Ojaula. Cont.: 08288853030
- SM 4 divorced Jat Boy (DOB 04.12.81) 35.6/5'11" M. Com, MFC, MBA, Own business. Family settled at Jai Pur Father retired from Rajasthan Govt. Originally from Rohtak (Haryana). Avoid Gotras: Tehlan, Budhwar, Hooda. Cont.: 09782178687
- SM 4 Jat Boy (DOB13.08.89) 31.7/6'1" MA, Mass Communications from London. Working in MNC Gurgaon with 12,5 lakh package PA. Avoid Gotras: Dahiya, Ahlawat. Cont.: 09717616149
- SM 4 Jat Boy 29/5'11" MBBS, MS Artho. Working in Government Hospital. Avoid Gotras: Dahiya, Nandal. Cont.: 09812043188
- SM 4 HPCL Hr. Officer (DOB 11.11.89) B.Tech, MBA. Package Rs. 12 lakh. Avoid Gotras: Kharb, Dabas, Bhanwala. Cont.: 09728576011
- SM 4 Jat Boy 30/5'9" B.Tech, MBA (UK) Marketing Manager, 60 lacks PA. Avoid Gotras: Tomar, Poriya. Cont.: 09412834119
- SM 4 Jat Boy 30/5'10" MBA Working in MNC, CTC 14Lpa, Preferred B.Tech, MBA/Lecturer. Avoid Gotras: Panwar, Kadian, Dalal. Cont.: 09810280462
- SM 4 Jat Boy Oct.89, 5'10" B.Tech. CS. Working in Nida, MNC, Preferred working girl. Avoid Gotras: Nain, Sirohi. Cont.: 09810983708
- SM 4 Jat Boy 30/5'8" M.D.(Radio) AIIMS, Working in U.S.A. Preference M.D, IIT/IIM girl. Cont.: 09520663598
- SM 4 Jat Boy (DOB 30.08.84) 32.8/6'4" B. Tech. Electronics & communications. Employed as Assistant Manager in Nationalized Bank. Parents retired Government officers. Avoid Gotras: Ahlawat, Malik, Sangwan. Cont.: 09417496903
- SM 4 Jat Boy (DOB 30.09.89) 27.6/5'10" B. Tech. Computer Engineering. Two flats and one showroom in Gurgaon. Father retired Principal. Avoid Gotras: Sheokand, Malik, Punia. Cont.: 09871044862
- SM 4 Jat Boy (DOB 28.10.85) 31.4/5'11" MBBS, M.S. from PGI Rohtak. Posted at Bhalot (Rohtak) as regular Medical Officer. Preference M.D.,MBBS match. Avoid Gotras: Malik, Phogat, Antil. Cont.: 09416770274
- SM 4 Jat Boy (DOB 28.10.90)26.10/5'11" BDS, MDS. Father S.D.O. retired from Haryana Government. Avoid Gotras: Malik, Phogat, Antil. Cont.: 09416770274
- SM 4 Jat Boy (DOB 01.08.85)31.6/6'1" M.A.,Mass Communication from London (England). Employed in MNC Company at Gurgaon with Rs.12.50 Lakh Package PA. Avoid Gotras: Dahiya, Ahlawat. Cont.: 09717616149
- SM 4 Jat Boy (DOB Nov.1989) 27.1/6' B.Sc in Hospitality & Hotel Administration. Occupation Hotel Industries in Dubai Package Rs. 10 lakh P.A. Father, Mother Haryana Govt. Employees at Panchkula. Avoid Gotras: Kundu, Dahiya, Tomar (Not direct Sangwan, Bhanwala). Cont.: 09416272188, 09560022263, 09416504181
- SM 4 Jat Boy 30/6' B.Tech. from P.E.C. Chandigarh. Employed in Jindal Steel Ltd. with Package Rs. 8.5 lakh P.A. Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Dhariwal, Lather, Basati. Cont.: 09592383356
- SM 4 Jat Boy 25/5'8" B.Tech from PEC Chandigarh Employed as Inspector in Custom & Central Excise (C.G.S.Bombay). Avoid Gotras: Poonia, Lohan, Rathee. Cont.: 08950492573
- SM 4 Jat Boy (DOB 04.12.90) 26/6' B.Tech Employed in Pb. & Sind Bank as P.O. at Jalandhar, Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Nain, Brar, Beniwal. Cont.: 09467037995, 09416048202
- SM 4 Jat Boy (DOB 15.04.91) 25.8/5'9" M.A. Employed as Clerk in SBI Panchkula. Avoid Gotras: Malik, Kundu, Saroha. Cont.: 08813089176
- SM 4 Jat Boy (DOB 23.08.89) 27.4/5'10" B.Tech. Employed as Service Engineer in Tata Motor Ltd. In Haryana. Avoid Gotras: Kundu, Malik, Rathee. Cont.: 08950092430
- SM 4 Jat Boy (DOB 25.11.87) 29./5'9" 10+2 Employed as Data Operator in UT Chandigarh on contract basis. Avoid Gotras: Hooda, Rathee, Kadian. Cont.: 09463457433
- SM 4 Jat Boy (DOB 21.04.90) 26.8/5'9" B.Tech Employed as Assistant in Haryana Civil Secretariat in Excise & Taxation Deptt. Only son, Father & Mother Gazzeted Officer in Haryana Govt. Avoid Gotras: Mor, Siwach, Singroha. Cont.: 09988701460
- SM 4 Jat Boy 28/5'10 B.A. PGDCA from P.U. Chandigarh. Employed in Punjab Coop. Bank as Regular D.E.O Father in Haryana Govt., Own Flat at Panchkula. Tri-city match preferred. Avoid Gotras: Gill, Nandal, Bazar. Cont.: 09876875845
- SM4 h'some Jat boy 28/6'1" Defence Family Seek Convt Sc. Stream Girl prfd. Avoid : Balhara, Ahlawat, Dalal, Mob.: 9801403959
- Tall b'ful well qualified, 91/6'1", B.Tech, IIT, wrkg girl 4 at h some boy CTC 22 Lpa, wrkg- Gurgaon, Email : shivaa957@gmail.com
- SM4 Smart Sat boy 31/6' B. Tech wrkg in IMINC at Delhi, 7.5 Lpa Edu family NCR. Avoid: Gotra, Balivan, Thanua. Contact: 9811787257
- SM4 Jat boy 30/ 5'10", MBA wrkg in MNC, CTC 14 Lpa. S. Delhi bsd pref. B.Tech/MBA/Lecturer from Edu & Rep. family. Avoid : Gotra, Panwar, Kadyan, Dalal. Mob: 9810280462.
- SM4 Jat v. h'some boy 26/179 BE & MBA (IIM), Own Two Internation School, Gurgaon, Delhi. Contact No.: 0124-4075510
- SM4 h'some Jat boy 32+/ 6' 1" M.Tech. (ECE), wrkg as AGM, telecom. 15 lpa Ftr. sr. ofr.(retd) bsd pref. B.Tech, MBA/Lecturer frm Eda & Rep. family. Avoid : Chhikara, jnon, dalal. Mob.: 09416053 741
- SM4 Tall & h'some,Jat boy 29/6' LLB, working MNC, Bangalury as In house Counssel, Pkg 27 LPA, Father (Retd.) GGM, Central PSU, Highly Educated Delhi based family, Seek b'ful & tall educated, Wrkg girl from good family background. Avoid : Kharb, Dhankar, Mob.: 9891000814.
- SM4 Jat boy 29/5'10", MBA-IIM, CA & B.Com, SRCC, CTC 27 L, Father & Brother CA, bsd pref. B.Tech/MBA/Lecturer from Edu & Rep. family. Avoid : Lakra, Ahlawat. Mob.: 9971380593

अहंकारी का विनाश जरूर होता है। –तुलसीदास

जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा आन दी स्पाट निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित

जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा ४ जुलाई, २०१७ को मोती राम आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैक्टर २७ चंडीगढ़ के इलावा हरियाणा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों-चौ० भरत सिंह यादगार खेल स्कुल, निडानी जिला जींद, भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कुल निडानी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना जिला जींद, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामलो कलां जिला जींद, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लजवाना कलां, जिला जींद, शिव वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गतोली जिला जींद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जुलाना जिला जींद, कन्या गुरूकुल शादीपुर, जुलाना जिला जींद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किला जफ्गढ़ जिला जींद, ज्ञानदीप माडल स्कुल सैक्टर १८ पंचकुला, सी एल डी ए वी पब्लिक स्कूल सैक्टर ११ पंचकुला व भवन विद्यालय सैक्टर १५ पंचकुला में आयोजित की गई भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार अखिल भारतीय आन दी स्पाट निबंध लेखन प्रतियोगिता में हरियाणा व चंडीगढ़, मोहाली के विभिन्न कालेजों व स्कूलों के लगभग १५०० विद्यार्थियों ने भाग लिया।

जाट सभा द्वारा यह प्रतियोगिता हर वर्ष सभा के प्रधान डा० एम०एस०मलिक आईपीएस (सेवा निवृत) के दिवंगत बहु प्रतिभाशाली पुत्र की यादगार में आयोजित की जाती है जो कि स्कूलों व कालेजों के विद्यार्थियों में शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार के प्रति रूची उत्पन्न करने के इलावा उनको अपनी प्रतिभा तथा विवेक द्वारा लेखन कला व शैक्षणिक दक्षता का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्रदान करती है।

सभा के प्रधान व हरियाणा के पूर्व पुलिस महा निदेशक एम०एस०मलिक आईपीएस (सेवा निवृत) ने चौ० भरत सिंह यादगार खेल स्कुल, निडानी जिला जींद व भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कुल निडानी केंद्रों पर निबंध के आन दी स्पाट विषय- 'ऊर्जा का सरंक्षण-समय की आवश्यकता' या 'क्या वर्तमान युवा भारत को एक महाशक्ति बनाने की दिशा में योगदान कर सकते हैं? या 'टी०वी० पर वास्तविक प्रतियोगिता (रियलिटी शो) में भाग लेने वाले बच्चों का भविष्य' की घोषणा करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया तथा ज्ञानदीप माडल स्कूल सैक्टर १८ पंचकुला केंद्र पर श्रीमती सारिका मलिक, ड्रग कंट्रोलर, युटी चंडीगढ़ द्वारा इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। परीक्षार्थियों को हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में निबंध लिखने की छूट प्रदान की गई और प्रतियोगिता को ग्रामीण व शहरी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया।

इस प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विशेषज्ञों द्वारा उ8ार पुस्तिकाओं की जांच के बाद की जाएगी और परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के इलावा प्रतियोगियों को डाक द्वारा भी प्रेषित किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को २२ जनवरी २०१८ को बंसत पंचमी तथा स्वतंत्रता पूर्व के समय के किसान तथा गरीब वर्ग के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध नेता दीन बंधू सर छोटु राम की जयंती समारोह के अवसर पर जाट भवन चंडीगढ़ में स6मानित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर्ता को ५१०० रूपये व स्वर्ण पदक, द्वित्तीय व तृतीय स्थान पाने वालों को क्रमशः ३१०० व रजत पदक तथा २१०० रूपये व कांस्य पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके इलावा प्रत्येक श्रेणी में ६०० रूपये प्रत्येक के ६ सांत्वना पुरूषकार भी प्रदान किए जाएंगें। इस प्रतियोगिता का सारा खर्च 'भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान निडानी' जिला जींद द्वारा वहन किया जाता है।

सम्पादक मंडल

संरक्षक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सम्पादक : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)
सह-सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़
जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172-2654932 फैक्स : 0172-2641127
Email : jat_sabha@yahoo.com

Postal Registration No. CHD/0107/2015-2017

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सम्पादक गुरनाम सिंह ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172-2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।